RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 132
दि. 11.09.2025, गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

पीएम ने भारत-अमेरिका संबंधों की मजबूती की पुष्टि की

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-अमेरिका संबंधों की आज मजबूती की पुष्टि की और दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वाताओं में विश्वास व्यक्त किया। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने देशवासियों के उज्जवल और समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

श्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के सोशल मीडिया एक्स पर की गई एक पोस्ट का उत्तर देते हुए कहा:

ह्लभारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को प्रदर्शित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारी टीम इन चचाओं को शीघ्र अति शीघ्र पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रम्प से बात करने के लिए भी उत्सुक हूँ। हम अपने दोनों देशों के लोगों के उज्जवल और समृद्ध भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही व्यापार वार्ता में 'सफल परिणाम' निकलेगा. उन्होंने आगे कहा कि वे आने वाले हफ्तों में अपने 'बहुत अच्छे दोस्त' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं.

'अपने दोस्त पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक'

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं. उन्होंने कहा, 'मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त,

प्रधानमंत्री मोदी से आगामी हफ्तों में बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं. मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए इस वार्ता का सफल निष्कर्ष निकलेगा.'

भारत-अमेरिका संबंधों को बताया था 'खास'

इससे पहले शनिवार को ट्रंप ने अमेरिका-भारत संबंधों को 'खास' बताया और अपने और पीएम मोदी के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया. ट्रंप ने कहा, 'मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा. वह एक महान प्रधानमंत्री हैं. मैं हमेशा दोस्त रहूंगा, लेकिन मुझे फिलहाल जो वह कर रहे हैं, वह मुझे पसंद नहीं है. लेकिन भारत और अमेरिका का संबंध बहुत खास है. चिंता की कोई बात नहीं है. बस कभी-कभी हमारे बीच थोड़े मतभेद हो जाते हैं.'

जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं गहराई से सराहना करता हूं और इसे पूरा स्वीकार करता हूं. भारत और अमेरिका के बीच बहुत सकारात्मक और भविष्य की ओर देखने वाली व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है.'

इजराइल के वित्त मंत्री श्री बेजेलेल स्मोट्रिच तथा प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

इजराइली वित्त मंत्री ने गिफ्ट सिटी में निवेश, फाइनेंशियल प्रोटोकॉल तथा यूपीआई जैसे विषयों में विशेष रुचि दिखाई

गुजरात का इजराइली टपक सिंचाई तथा विकास परियोजनाओं में सकारात्मक दृष्टिकोण : मुख्यमंत्री

आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टोलरेंस नीति के साथ लड़ाई के लिए भारत-इजराइल प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री

गांधीनगर, 10 सितंबर : इजराइल के वित्त मंत्री श्री बेजेलेल स्मोट्रिच तथा प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की।

इजराइली वित्त मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। इस दौरान वे गुजरात की यात्रा पर आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ यह भेंट-बैठक आयोजित की।

श्री स्मोट्रिच ने भारत-गुजरात तथा इजराइल के बीच हेरिटेज, ट्रेडिशन, कल्चर तथा टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में समानता होने का उल्लेख करते हुए इस संबंध की व्यापकता को भविष्य में और सुदृढ़ बनाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के साथ फलदायी परामर्श किया।

उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जैसे प्रतिभाशाली राष्ट्र पुरुष की जन्मभूमि निहारने की आकांक्षा के साथ गुजरात में बिजनेस टु बिजनेस रिलेशन्स विकसित करने तथा गिफ्ट सिटी जैसे अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल सेंटर में इजराइल के वित्तीय संस्थानों के प्रबंधन की संभावनाओं को लेकर विशेष रूप से गुजरात यात्रा पर आए हैं।

उन्होंने जोड़ा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा इजराइल के प्रधानमंत्री के ऊष्मापूर्ण व्यक्तिगत संबंध एवं आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए दोनों की प्रतिबद्धता से दोनों देश अधिक निकट आए हैं। इतना ही नहीं; श्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने भारत द्वारा इजराइल को लगातार दिए गए सहयोग की भी प्रशंसा की। उन्होंने यूपीआई के उपयोग तथा फाइनेंशियल प्रोटोकॉल के बारे में जानने की रुचि दर्शाई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने विशेष उल्लेख किया कि इजराइल के साथ भारत के संबंध प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में प्रगाढ़ बने हैं और आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टोलरेंस की नीति पर इजराइल भी बहुत दृढ़ता से आगे बढ़ा है।

प्रधानमंत्री 11 सितंबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 सितम्बर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का दौरा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में लगभग 11:30 बजे मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की मेजबानी करेंगे जो 9 से 16 सितंबर 2025 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं।

इसके बाद प्रधानमंत्री देहरादून जाएंगे और शाम लगभग 4:15 बजे उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। शाम लगभग 5 बजे, प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

ऐतिहासिक शहर वाराणसी में दोनों नेताओं के बीच होने वाली बैठक स्थायी सभ्यतागत संबंध, आध्यात्मिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे बंधनों को रेखांकित करती है, जिसने भारत और मॉरीशस के बीच विशेष और अद्वितीय संबंधों को आकार दिया है।

द्विपक्षीय चचाओं के दौरान, दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे जिसमें विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वे स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और नीली अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा करेंगे।

यह यात्रा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस की राजकीय यात्रा से उत्पन्न सकारात्मक माहौल पर आधारित है जिसके दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को 'संवर्धित रणनीतिक साझेदारी' तक बढ़ाया था।

हिंद महासागर क्षेत्र में एक मूल्यवान साझेदार और घनिष्ठ समुद्री पड़ोसी के रूप में, मॉरीशस भारत के 'महासागर' (क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक व समग्र उन्नति) दृष्टिकोण और 'पड़ोसी पहले' नीति के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच मजबूत होता सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों की समृद्धि के लिए बल्कि ग्लोबल साउथ की सामूहिक आकांक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से फोन पर बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इटली की प्रधानमंत्री सुश्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।

दोनों नेताओं ने निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, लोगों के बीच संबंध और आतंकवाद-निरोधक जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में हुए विकास की समीक्षा की और उसका सकारात्मक मूल्यांकन किया। दोनों नेताओं ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 के अनुरूप साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

नेपाल आंदोलन के बीच कैलाश मानसरोवर में फंसे 2000 भारतीय तीर्थयात्री, दारचेन समुद्र तल से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ऑक्सीजन खत्म!

(जीएनएस)।

नेपाल में चल रहे Gen Z आंदोलन के चलते तिब्बत के दारचेन में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सैकड़ों भारतीय तीर्थयात्री मुसीबत में फंस गए हैं। इस आंदोलन की वजह से तीर्थयात्रियों की भारत वापसी फिलहाल असंभव दिख रही है। दारचेन समुद्र तल से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी इलाका है, जहां रहने के लिए जगह, ऑक्सीजन और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है।

ऑक्सीजन सपोर्ट में मुश्किल

दारचेन में फंसे केरल के त्रिशूर निवासी डॉ. सुजॉय सिधन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा, "दारचेन एक सीमित आवास वाला शहर है। परिक्रमा के बाद लौटने वाले लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट वाले

कमरों की जरूरत होती है। हम जैसे लोग, जिन्होंने परिक्रमा पूरी कर ली है, दूसरों के लिए जगह नहीं बना पा रहे।"

स्थानीय चीनी अधिकारी कुछ तीर्थयात्रियों को चीन-नेपाल सीमा पर स्थित छोटे शहरों में भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है।

अचानक बंद हुई सीमाएं

सिधन और उनके साथ ग्रुप में गए लोगों ने नेपाल के एक निजी ऑपरेटर के माध्यम से यात्रा शुरू की थी। तीन दिन पहले उन्होंने मानसरोवर की परिक्रमा पूरी की थी। इसी बीच नेपाल में हालात अचानक बिगड़ गए, जहां ञ्जल्ल` आंदोलन ने सरकार को गिरा दिया और सीमाएं बंद हो गईं। अनुमान है कि दारचेन में इस समय लगभग 2,000 तीर्थयात्री, जिनमें अधिकांश भारतीय हैं, फंसे हुए हैं और वापसी को लेकर बुरी तरह फंसे हुए हैं। न उनके सामने कोई विकल्प है और न कोई मदद।

अब तक नहीं पहुंची मदद

सूत्रों के अनुसार, बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास चीनी अधिकारियों के संपर्क में है और वापसी के विकल्पों पर विचार कर रहा है। हालांकि, तीर्थयात्रियों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है।

सिधन ने चिंता जताते हुए कहा, "हर कोई नेपाल में फंसे भारतीयों की बात कर रहा है, लेकिन दारचेन में 2,000 से अधिक भारतीय नागरिक बदतर परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। इनमें से कई बुजुर्ग हैं या पहाड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत है।"

नेपाल ने बंद किए सभी रास्ते

भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। सरकारी एजेंसियां सिक्किम और उत्तराखंड से लगभग 750 तीर्थयात्रियों को ले गईं थीं। वहीं, हजारों अन्य तीर्थयात्रियों ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से यात्रा की, जिनका मार्ग नेपालगंज-हिल्सा-दारचेन होता है। यही मार्ग वापसी का एकमात्र विकल्प है, लेकिन नेपाल की सीमा बंद होने के कारण यह अब बंद हो गया है।

और बढ़ सकती है समस्या

सिधन ने बताया कि लगातार अधिक लोग परिक्रमा पूरी करके लौट रहे हैं, जिससे दारचेन में स्थिति और बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को भारतीय अधिकारियों का फोन आया था, लेकिन उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि "हम अब अपनी वापसी की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय से समर्थन की तलाश कर रहे हैं,"

फिलहाल इस मामले पर सरकार की तरफ से कुछ ठोस कदम सामने नहीं आया है।

केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान पर समीक्षा बैठक की

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन

के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान पर केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय राज्यमंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा और अन्य अधिकारियों के साथ आज दिल्ली में समीक्षा बैठक की।

अति वृष्टि और बादल फटने के कारण राजमार्गों को हुए भारी नुकसान पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों समाधान निकालने पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए।

लोक सभा अध्यक्ष बेंगलुरु में 11वें सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

कर्नाटक के राज्यपाल, कर्नाटक के मुख्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँगे

11-13 सितंबर को आयोजित होने वाले सम्मेलन का विषय है "विधानमंडलों के सदनों में वाद-विवाद और चर्चा: जन विश्वास का निर्माण, जन आकांक्षाओं की पूर्ति"

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, 10 सितंबर 2025: लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, जो सीपीए भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं, 11 सितंबर 2025 को बेंगलुरु स्थित विधान सौध में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है "विधानसभा के सदनों में वाद-विवाद और चचाएँ: जन विश्वास का निर्माण, जन आकांक्षाओं की पूर्ति"। विदेशी संसदों के पीठासीन अधिकारियों के साथ-साथ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अध्यक्ष और महासचिव को भी सम्मेलन में आमंत्रित

किया गया है।

विधान सौध में आयोजित किए जा रहे उद्घाटन समारोह में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के सभापतियों/अध्यक्षों सहित पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे।

उद्घाटन सत्र के दौरान, कर्नाटक के मुख्य मंत्री, श्री सिद्धारमैया; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित विशिष्टजनों को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष, श्री यू.टी. खादर फरीद स्वागत भाषण देंगे तथा सीपीए कर्नाटक शाखा के सचिव धन्यवाद ज्ञापित करेंगे।

कर्नाटक के राज्यपाल, श्री थावर चंद गहलोत और लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 13 दिसंबर 2025 को समापन सत्र को संबोधित देंगे।

इस तीन दिवसीय कार्यक्रम (11-13 सितंबर) का आयोजन सीपीए कर्नाटक शाखा के तत्वावधान में कर्नाटक विधान सभा द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री बिरला एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।

रक्षा मंत्री की चेतावनी के बाद सलमान खान ने लिया यू-टर्न

(जीएनएस)।

सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग अब फाइनली शुरू हो गई है। सेट से सलमान खान की फोटो भी आई थी। जिसके बाद उनका लुक भी रिवील हो गया था। इस फिल्म शूटिंग के शुरू होने में काफी दिक्कत आई हैं। इसकी शूटिंग शुरू करने के लिए सलमान खान रक्षा मंत्री से भी मिलना पड़ा था।

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। फिल्म की शूटिंग में परेशानियां आ रही थीं। इसको लेकर उन्होंने चर्चा की। जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको हिदयात दी है। जिसके बाद ये सवाल ये उठ रहा है कि सलमान खान अपनी फिल्म कहानी में कुछ बदलाव कर रहे हैं या नहीं?

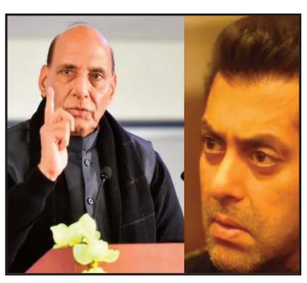

सलमान खान को हिदायत देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि फिल्म की कहानी में किसी भी तरह से चीन को बदनाम न किया जाए। क्योंकि इन दिनों भारत और चीन के ग्लोबल लेवल पर रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच अब रिश्तों में सुधार भी आ रहा है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि सलमान ने भी रक्षा मंत्री को विश्वास दिलाया कि कहानी में सिर्फ भारतीय

सेना का गौरव दिखाया जाएगा। फिल्म किसी भी एंगल से एंटी चाइना नहीं रहेगी। बता दें, फिल्म 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित बताई जा रही थी। इसमें चीन और भारत की सेना की झड़प हुई थी, जिसमें कई सैनिक शहीद हुए थे। ऐसे में सलमान के अब अपनी कहानी में कितना बदलाव करते हैं। अगर फिल्म एंटी चाइना नहीं होगी, तो क्या सलमान तथ्य में भी फेरबदल करेंगे? इस तरह के कुछ सवाल हैं? जिनके जवाब ऑफिशियली कब मिलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।

बता दें, सलमान इस फिल्म में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। जो इस झड़प में शहीद हुए थे। कर्नल बी संतोष बाबू (महावीर चक्र) 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल बाबू 2020 में चीन-भारत झड़प के दौरान कार्रवाई में शहीद हुए थे। उनका जन्म 1982 में सूयार्पेट तेलंगाना में हुआ था। उनके पिता एक बैंकर और मां होममेकर थीं। उनकी शुरूआती पढ़ाई कोरुकोंडा स्थित सैनिक स्कूल में हुई।

उपराष्ट्रपति निर्वाचन 2025

आयोग ने 1 अगस्त, 2025 के अपने प्रेस नोट के माध्यम से सत्रहवें उपराष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 9 सितंबर, 2025 को मतदान और मतगणना की तिथि निर्धारित की गई थी। निर्धारित कार्यक्रम

के अनुसार, 9 सितंबर, 2025 को कमरा संख्या एफ-101, वसुधा, प्रथम तल, संसद भवन, नई दिल्ली में मतदान हुआ। कुल 781 मतदाता जो मतदान के पात्र थे, उनमें से 767 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें से 15 मतपत्र अवैध घोषित कर दिए गए।

सम्पादकीय

नये जोश को तरसता विपक्ष

जो है, जैसा है कब तक चलता रहेगा? शायद बरसों-बरस से एक ही चेहरा देख रहे लोग कांग्रेस से मुंह मोड़ रहे हैं, नए लोग खासकर युवा पीढ़ी इसीलिए नहीं जुड़ पा रही है। कांग्रेस के तमाम सहसंगठन भी कागजी होकर रह गए हैं। संगठित होना फिर कब सीखेगी कांग्रेस? कांग्रेस में अंर्तकलह है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बावजूद इसके राहुल गांधी संगठन के लिए रात-दिन एक किए हुए हैं। इससे राहुल की छवि यकीनन बदली है। उन्हें गंभीरता से लिया जाना बताता है कि कांग्रेस के बुरे दिन जरूर हैं लेकिन पाटा में नया जोश भरने में वो पीछे नहीं है। लेकिन, क्या संगठन में मौजूद तमाम वरिष्ठ और जिम्मेदार भी यह समझेंगे? राहुल पाटा का सम्मानजनक आधार बनाने और समर्थक दलों से एकजुटता खातिर रात-दिन एक कर रहे हैं। उनकी तमाम यात्राएं या अभी बिहार में सव्रियता सामने है। लेकिन संगठन और कार्यकर्ता इसे क्यों नहीं समझ पा रहे? अभी मध्यप्रदेश में पांच बरस पहले सत्ता से बेदखल हुईं कांग्रेस में संगठन की हुईं नईं-नईं सर्जरी बाद जो घमासान मचा, वह नया नहीं था, अलबत्ता टाइमिग गलत रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 71 जिला अध्यक्षों की सूची जारी की। 21 को फिर जिम्मेदारी और 50 नए चेहरे लिए। 3 पूर्व मंत्री, 6 मौजूदा और 11 पूर्व विधायक सहित 4 महिलाओं, 12 ओबीसी, 10 एसटी, 8 एससी और तीन अल्पसंख्यकों को जिलों की कमान सौंपी गईं। इस पर तर्व-वितर्व, विरोध भी शुरू हो गया। पटवारी ने मान-मनव्वल किया। सोशल मीडिया पर लिखा कि सबके सर्वश्रेष्ठ योगदान से ही सशत्त संगठन मप्र कांग्रेस की पहचान बनेगा। वंचित रहे साथियों को जल्द नईं जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं बिना देरी सभी नव नियुत्त गुरुमंत्र देने के नाम पर दिल्ली तलब किए गए। वैडर प्रबंधन के टिप्स 9-ए, कोटला रोड स्थित नए कांग्रेस दफ्तर में दिए गए। राहुल लगभग एक घण्टा बोले और साफ कर दिया कि अगले 6 महीनों तक तक कोईं नहीं बदलेगा। सबका काम देखेंगे। नव नियुत्त दिल्ली से लौटे नहीं कि मध्यप्रदेश के दो दिग्गजों की सोशल मीडिया जंग ने नया रंग ले लिया। पुराने जख्म वुरेदे जाने लगे। मार्च-2020 में ज्योतिरादित्य सिधिया के भाजपा में जाने से मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरी थी। जबकि 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल की हर रैली के दाएं-बाएं कमलनाथ औ ं सिधिया ही दिखते थे। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि सिधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिह चला रहे हैं। इसी नाराजगी से कांग्रेसी विधायकों को तोड़ सरकार गिरा दी गईं। वहीं दिग्विजय सिह, कमलनाथसिधि या के बीच ग्वालियर-चंबल मुद्दों पर सहमति न बन पाना सरकार गिरने की वजह बताते हैं। सच जो भी हो वही जानें। लेकिन संदेश अच्छा नहीं गया। उधर 2020 और उसके बाद कांग्रेस सरकार गिरने के बाद हुए कईं स्थानीय निकायों या ऐसे दूसरे चुनावों में साफ बहुमत के बावजूद कांग्रेस को जगह-जगह क्यों शिकस्त मिली? इसका जवाब न तो किसी कांग्रेसी के था न ही वो फॉमूर्ला जिसने जीतकर भी बैकपुट पर पहुंचाये। समझकर, जानकर भी ऐसे जनप्रतिनिधि ढ़ोना मजबूरी बनीं। हालाकि कईं मौका देखते ही पाटा से दगा कर गए। आलाकमान की इस पर चिता जरूर समझ आती है। इंदिरा जी के कार्यर्काल में और उनके बाद भी बगावत दिखती थी। लेकिन हर बार पाटा बिखरती, उबरती, टूटती और फिर जुटतीजुड़ ती रही। लेकिन ये क्या, 2014 के बाद संगठन में बिखराव और दिग्गजों का जो रूठना-टूटना शुरू हुआ, रुक नहीं रहा है। लगता नहीं कि संगठन में अनुशासन की पाठशाला के जो शिक्षक हैं वो या तो ट्रेन्ड नहीं है या वत्त बिता रहे हैं? सोचिए भला उस प्रदेश में जिसके लिए चंद घण्टे पहले अनुशासन की इबारत और संगठन की लंबी क्लास चली, वहीं पलक झपकते दिग्गज ही सब वुछ भुला दें? एक ही पाटा के दो पूर्व मुख्यमंत्री बाहें चढ़ा मैदान में वाकयुद्ध की तलवार भांजते नजर आएं! हिमाचल और कर्नाटक में भी जो खींचतान और तल्खी दिखती है वह जगजाहिर है। अन्य प्रदेशों में भी संगठन का कमोवेश यही हाल है। पाटा शुद्धिकरण की नीयत से राहुल का वो बयान काबिल-एतारीफ है जिसमें उन्होंने रेस के घोड़ों को बारात में और बारात के घोड़ों को रेस में दौड़ाने जैसी बात कहकर संगठन पर ही उंगली उठा बड़े बदलाव का संकेत दिया था।

लगभग 66 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात की साणंद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 66 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया

राधाकृष्णन जी के निर्वाचन के साथ ही भारत के संवैधानिक पदों पर देश की भौगोलिक एकता की जीत हुई

देश के संवैधानिक पदों पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है

वर्ष 2029 तक साणंद विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गाँव बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा

आने वाले समय में साणंद पूरे गुजरात में औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित तहसील बनेगी

साणंद में जल्द ही सेमीकंडक्टर यूनिट का काम भी शुरू होने जा रहा है

मोदी जी के "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गाँव, स्कूल, और नगरपालिका की खाली जगहों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो

पूरे गुजरात में सर्वाधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड गांधीनगर लोकसभा ने बनाया है

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के साणंद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 66 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि कल ही संपन्न हुए देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में, अन्य सभी चुनावों की तरह, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ठऊअ उम्मीदवार श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन जी के निर्वाचन के साथ ही भारत के संवैधानिक पदों पर देश की भौगोलिक एकता की जीत हुई है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पूर्वी भारत से हैं, उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी दक्षिण भारत से हैं, और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, जो गुजरात से हैं और वाराणसी से चुनाव जीते हैं, पश्चिम और उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार, देश के संवैधानिक पदों पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से साणंद को एक निश्चित योजना के साथ विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 तक साणंद विधानसभा क्षेत्र का कोई भी गाँव बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि बावला और साणंद नगरपालिका में सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है। इस क्षेत्र में सड़क, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल जैसी सुविधाएं पहले से अधिक सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि जब धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन शुरू हो जाएगा और साणंद क्षेत्र के आसपास औद्योगिक विकास कार्य पूर्ण हो जाएँगे, तब साणंद पूरे गुजरात में औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित तहसील बनेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार द्वारा इसकी योजना बनाई जा चुकी है।

श्री अमित शाह ने कहा कि साणंद के 111 गाँवों में वर्षों से सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से गाँवों तक पानी पहुँचाने का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही घरों और खेतों तक पानी पहुँचाने का कार्य लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से पुनः शुरू होगा। श्री शाह ने कहा कि साणंद विधानसभा क्षेत्र में उरफ (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) के माध्यम से लगभग 150 करोड़ रुपए के कार्यों की योजना बनाई गई है। प्रत्येक गाँव की आवश्यकताओं की पहचान कलेक्टर, विधायक और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले उद्योगपतियों के साथ हुई उनकी चर्चा के आधार पर एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से साणंद के गाँवों में जो बुनियादी सुविधाएँ नहीं हैं उन्हें अगले डेढ़ से दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे मोदी जी के "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के अंतर्गत प्रत्येक गाँव, स्कूल, और नगरपालिका की खाली जगहों पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। उन्होंने कहा कि ग्रीन गांधीनगर प्रोजेक्ट के तहत गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में प्रतिदिन वृक्षों की संख्या बढ़ रही है। श्री शाह ने कहा कि पूरे गुजरात में सर्वाधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड गांधीनगर लोकसभा ने बनाया है, जो प्रसन्नता का विषय है।

श्री अमित शाह ने कहा कि हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने भारत के पहले पूर्ण विकसित 32-बिट प्रोसेसर चिप 'विक्रम-32' का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि साणंद में भी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी द्वारा चिप निर्माण का काम शुरू किया जाने वाला है। इस सेमीकंडक्टर यूनिट के कारण साणंद के विकास में एक नया आयाम जुड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज के कार्यक्रम में 29 कार्यों का लोकार्पण हुआ, 23 कार्यों का भूमिपूजन हुआ, और लगभग 66 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरूआत हुई या वे पूरे किए गए। इनमें वृक्षारोपण, सड़क निर्माण, ग्रामीण सड़क योजना, गाँव की सड़कें, स्कूलों का विकास जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं।

"आदि संस्कृति" के बीटा संस्करण की शुरूआत

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातियों के कलारूपों के डिजिटल शिक्षण के लिए एक मंच, "आदि संस्कृति" के बीटा संस्करण की शुरूआत की

प्रत्येक जनजातीय गीत, कहानी, कार्य प्रणालियों के ज्ञान को संरक्षित करने, उनके अध्ययन, प्रगति और आजीविका के लिए एक मंच तैयार

(जीएनएस)।

परंपरा को तकनीक से जोड़ते हुए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आदि कर्मयोगी अभियान पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान, आदिवासी कलारूपों, विरासत के संरक्षण, आजीविका को सक्षम बनाने और भारत के जनजातीय समुदायों को दुनिया से जोड़ने के लिए एक अग्रणी डिजिटल शिक्षण मंच, आदि संस्कृति के बीटा संस्करण की शुरूआत की। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, दुगार्दास उइके ने इस मंच का औपचारिक

शुभारंभ किया, जिससे आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नए डिजिटल युग की शुरूआत हुई।

आदि संस्कृति की कल्पना जनजातीय समुदायों की संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने, और जनजातीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों तक दुनिया भर की पहुँच प्रदान करने वाले एक ऑनलाइन बाजार के लिए दुनिया के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय के रूप में की गई है। इस प्लेटफॉर्म में तीन प्रमुख घटक शामिल हैं:

आदि विश्वविद्यालय (डिजिटल ट्राइबल आर्ट अकादमी): वर्तमान में आदिवासी नृत्य, चित्रकला, शिल्प, संगीत और लोककथाओं पर 45 इमर्सिव पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है।

आदि सम्पदा (सामाजिक-सांस्कृतिक भंडार): पांच विषयों पर 5,000 से अधिक संकलित दस्तावेजों का संग्रह, जिसमें चित्रकला, नृत्य, वस्त्र एवं वस्त्र, कलाकृतियाँ और आजीविका शामिल हैं

आदि हाट (ऑनलाइन बाजार): वर्तमान में ट्राइफेड के साथ जुड़ा हुआ, यह आदिवासी कारीगरों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन बाजार के रूप में विकसित होगा, जिससे स्थायी आजीविका और प्रत्यक्ष उपभोक्ता पहुँच संभव होगी।

राज्य टीआरआई के साथ तालमेल से निर्माण

आदि संस्कृति का निर्माण राज्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के साथ घनिष्ठ साझेदारी में किया जा रहा है, जिससे इसके विकास में जमीनी स्तर की भागीदारी, प्रामाणिकता और तालमेल सुनिश्चित हो सके। इसके पहले चरण में, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के टीआरआई ने जनजातीय कलाकृतियों के दस्तावेजीकरण, विषयवस्तु संग्रह और डिजिटल मानचित्रण में योगदान दिया है। इस सामूहिक प्रयास ने एक ऐसे मंच की नींव रखी है जो भारत की जनजातीय विरासत की विविधता और समृद्धि को दशार्ता है।

शुरूआत के समय अभिव्यक्तियां

इस अवसर पर जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, श्री दुगार्दास उइके ने अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और उनकी विरासत के संरक्षण के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने जनजातीय भाषाओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-आधारित अनुवादक, आदि वाणी की पूर्व में की गई शुरूआत का जिक्र किया और आशा व्यक्त की कि ऐसे उपकरण जल्द ही लोकतांत्रिक मंचों और संस्थानों में उपयोगी साबित होंगे।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, "शिक्षा से संपदा और हाट तक - आदि संस्कृति संरक्षण, ज्ञान-साझाकरण और सशक्तिकरण का एक समग्र मंच है। यह जनजातीय समुदायों, उनकी संस्कृति और विरासत के बारे में विविध ज्ञान प्रदान करता है और कला रूपों के भंडार के रूप में कार्य करता है। इसके शुभारंभ के साथ, अब कोई भी जनजातीय संस्कृति, विरासत और आजीविका के खजाने से जुड़ सकता है।"

जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अनंत प्रकाश पांडे ने कहा कि आदि संस्कृति, विकसित भारत @2047 के लिए सांस्कृतिक संरक्षण और जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने लोगों से इस पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया, जो अब सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। उन्होंने इसके निरंतर संवर्धन के लिए फीडबैक साझा करने का भी आग्रह किया।

मंत्रालय ने पुष्टि की है कि आदि संस्कृति का विस्तार चरणबद्ध तरीके से और अधिक पाठ्यक्रमों, संग्रहों और बाजार एकीकरण के साथ किया जाएगा। दीर्घकालिक दृष्टिकोण इस प्लेटफॉर्म को एक जनजातीय डिजिटल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करना है, जो प्रमाणन, उन्नत शोध के अवसर और परिवर्तनकारी शिक्षण मार्ग प्रदान करेगा।

संरक्षण, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को एक साथ लाकर, आदि संस्कृति भारत के जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और उसका उत्सव मनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, साथ ही उन्हें डिजिटल ज्ञान अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदार के रूप में सशक्त भी बनाया गया है।

शहनाज हुसैन के खूबसूरती टिप्स।

तरबूज का जूस प्रयोग करें

तरबूज का जूस एक अच्छा सकिन टोनर है और रूखेपन को कम भी करता है। यह त्वचा को ठंडक, रिफ्रेश और कोमल बनाता है। इसका रस चेहरे पर 20 मिनट तक लगाएं और फिर पानी से धो लें। सभी ट वचा के लिये फ्रूट मास्क केला, सेब, पपीता और संतरा जैसे फलों को मिर्क स कर के मास्क बना कर चेहरे पर लगाएं। 30 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। इससे चेहरे को ठंडक पहुंचेगी, डेड सकिन साफ होगी और सन टैनिंग मिटेगी।

कूलिंग मास्क----------

खीरे के रस में 2 चम्मच पावडर वाला दूध और एक अंडे का सफेद भाग मिला कर पेस्ट बनाएं। इसे चेहरे और गरदन पर लगाएं और जब सूख जाए तब पानी से धो लें।

ऑइली ं किन के लिये मास्क------

1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिला कर पेस्ट बना कर चेहरे पर लगाएं। सूखने के बाद इसे पानी से धोलें।

टी बैग का प्रयोग ------

टी बैग भी अच्छा काम कर सकते हैं। इन्हें गरम पानी में कुछ देर के लिये डालें और निचोड़ कर आंखों पर आई पैड बना कर रखें।

रूखे, सूखे और बेजान बाल--------

पानी के साथ थोड़ा सा क्रीमी हेयर कंडीशनर मिला कर स्प्रे बॉटल में भर कर रखें। बालों पर इससे स्प्रे करें और फिर कंघी से बाल झाड़ कर पूरे बालों पर इसे फैला लें।

आई मेकअप -----------

दिन में हमेशा आई पेंसिल का प्रयोग करें या फिर पलको को ब्राउन या ग्रेड आई शैडो से लाइन करें। इससे आंखों को सॉफ्ट इफेक्ट मिलेगा। उसके बाद आंखों पर केवल एक या दो कोट्स मस्कारा के लगाएं। इससे आंखे गहरी और चमकदार दिखेंगी।

7 ---लिपसटिक-------

लिपसटिक के लिये बहुत गहरा रंग ना चुनें जैसे, महरून आदि। आपको लाइट पेस्टल कलर जैसे पिंक, लाइट ब्राउन, कॉपर या पीच रंगों का चुनाव करना चाहिये। या फिर केवल लिप ग्लॉस ही चुनें।

8 ----. खरबूज, पानी और ककड़ी गर्मी के सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ हैं

वास्तव में प्रकृति ने हमें ऐसे फल दिए हैं जिनका सेवन कर हम गर्मी को दूर कर सकते हैं। खरबूजे, तरबूजे, ककड़ी गर्मियों के दौरान उपलब्ध होते हैं। इन फलों में काफी पानी भरा रहता है। इनके सेवन से शरीर में मौजूद गंदा पानी पसीने के रास्ते बाहर निकल जाता है। अगर आपको गर्मियों के मौसम में आपको काफी पसीना आता है तो आप खरबूजे, तरबूजे और ककड़ी जैसे फलों का सेवन कर सकती हैं। इससे शरीर में पानी की कमी पूरी होती है।

9 ---- पुदीने के पत्ते, नींबू के साथ पानी और बर्फ

पुदीने के पत्ते में ठंडक होती है, जिससे पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। पुदीने को गर्म पानी में उबाल कर कुछ देर के लिए छोड़ दें। ठंडा होने पर एक चम्मच नींबू का रस ग्लास में डाल दें। इसके बाद ठंडक के लिए बर्फ इसमें डाल लें। इसे और उपयोगी बनाने के लिए इसमें शहद, नमक और काली मिर्च की कुछ मात्रा जोड़ लें। नमक और काली मिर्च ना हो तो ऐसे में आप सेंधा नमक और चाट मसाला का इस्तेमाल भी कर सकती हैं।

नेपाल में पीएम के इस्तीफे के बाद भी क्यों नहीं थम रहा विरोध, क्या हैं प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें

(जीएनएस)।

नेपाल इस समय अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे (ङढ रँ१ ङ' १ी२ॅ्ल्लं३्रङ्मल्ल) के बाद देश राजनीतिक अनिश्चितता में धकेल दिया गया है। सोशल मीडिया पर पाबंदी और भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों से शुरू हुआ विरोध अब हिंसक रूप ले चुका है।

बीते दिनों की झड़पों में कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बड़ी संख्या छात्रों की है। यह संकट नेपाल की नाजुक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

याद दिला दें कि नेपाल ने 2008 में राजशाही खत्म कर लोकतांत्रिक शासन अपनाया था। लेकिन मौजूदा हालात यह दिखाते हैं कि जनता, खासकर युवा, राजनीतिक नेतृत्व से बेहद असंतुष्ट है।

कैसे शुरू हुआ आंदोलन?

सोमवार को तब हालात बिगड़ गए जब सरकार ने फेसबुक, , यूट्यूब समेत 25 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सरकार ने कंपनियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने पंजीकरण और सरकारी नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया है।

लेकिन सेंसरशिप के खिलाफ शुरू हुआ यह विरोध जल्द ही भ्रष्टाचार, वंशवाद (ठीस्र्ङ्म३्र) और बेरोजगारी के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदल

गया। नेपाल से हर दिन करीब 2,000 युवा नौकरी की तलाश में विदेश जा रहे हैं, जिससे असंतोष और गहरा हो गया।

क्या है वहां के मौजूदा हालात?

सैन्य नियंत्रणः राजधानी काठमांडू में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कर्फ्यू लगाया गया है और उपद्रव रोकने के लिए चेतावनी स्वरूप हवाई फायरिंग की जा रही है। अब तक 27 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाहक सरकारः राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उन्हें तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा है जब तक नया नेता नियुक्त नहीं हो जाता। हालांकि, ओली की मौजूदा स्थिति पर असमंजस है और वे सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे।

संवाद की अपीलः सेना और शीर्ष अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए प्रतिनिधि मंडल बनाने को कहा है, लेकिन आंदोलन के लीडरलेस (नेतृत्वविहीन) होने के कारण यह चुनौतीपूर्ण है।

क्या बनेगी अंतरिम सरकार?

नेपाल का 2015 का संविधान इस स्थिति में स्पष्ट रास्ता दिखाता है कि राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे। यदि कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती, तो कोई भी सांसद जिसके पास बहुमत हो, प्रधानमंत्री बन सकता है। यदि 30 दिनों में विश्वासमत साबित नहीं होता, तो संसद भंग की जा सकती है और नए चुनाव कराए जा सकते हैं।

समस्या यह है कि मौजूदा राजनीतिक नेताओं को जनता पूरी तरह नकार रही है। कई नेता छुपने को मजबूर हैं या प्रदर्शनकारियों के हमले का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। संविधान में अंतरिम सरकार का जिक्र नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा हालात में यह जरूरी हो सकता है।

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। रिपोट्र्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े लोगों से इस बारे में चर्चा भी हुई है।

युवाओं का समर्थन किसके साथ?

आंदोलन के बीच दो नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं: बालेंद्र शाह (बालेन शाह): 35 वर्षीय काठमांडू मेयर और रैपर, जिन्हें भ्रष्टाचार विरोधी छवि और युवाओं के बीच लोकप्रियता के लिए जाना जाता

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी)-2025 के मसौदे पर प्रतिक्रिया आमंत्रित की

(जीएनएस)।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रसार हेतु मानक निर्धारित करने वाला नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय आंकड़ों की समयबद्धता, गुणवत्ता और विस्तृत जानकारी में सुधार के लिए कई संरचनात्मक सुधार कर रहा है। इनमें प्रमुख संकेतकों के आधार वर्ष को अद्यतन करना, स्थानीय स्तर पर आंकड़ों के संग्रह को सक्षम बनाने के लिए विभिन्न सर्वेक्षणों की कार्यप्रणाली को परिष्कृत करना और विभिन्न सांख्यिकीय वर्गीकरणों को अद्यतन करना शामिल है। मंत्रालय ने इन्हीं प्रयासों के तहत अब अपने राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी)-2008 को संशोधित किया है और एनआईसी-2025 का मसौदा तैयार किया है।

राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) सांख्यिकीय सर्वेक्षणों, जनगणनाओं, आर्थिक अनुसंधान, पंजीकरण प्रक्रियाओं और केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा नीति निर्माण सहित अनेक क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले एक आधारभूत उपकरण के रूप में कार्य करता है। भारत ने अपना पहला मानक औद्योगिक वर्गीकरण 1962 में जारी किया था। इसके बाद, अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिक वर्गीकरण (आईएसआईसी) में हुए संशोधनों के अनुरूप इसे नियमित रूप से संशोधित किया गया। इसी तरह, एनआईसी 1970, एनआईसी 1987, एनआईसी 1990, एनआईसी 1998, एनआईसी 2004 और एनआईसी 2008 में परिष्कृत किया गया।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा 2024 में आईएसआईसी संशोधन 5 को स्वीकृत और अपनाए जाने के बाद एनआईसी-2008 का व्यापक संशोधन आवश्यक हो गया। यह संशोधन भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए महत्वपूर्ण संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों के कारण भी आवश्यक था। इसमें नए उद्योगों, सेवाओं और तकनीकी प्रगति का उदय शामिल है। इनके लिए उचित समावेशन और प्रतिनिधित्व की भी आवश्यकता है।

एनआईसी-2025 का मसौदा एक विशेषज्ञ समिति के तत्वावधान में तैयार किया गया है। इसमें प्रख्यात शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, उद्योग संघ और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, उद्योग विशेषज्ञों और अन्य संबंधित संगठनों सहित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श भी किया गया।

विभिन्न देशों के आंकड़ों की तुलना सुनिश्चित करने के लिए एनआईसी-2025 का मसौदा आईएसआईसी संशोधन 5 के अनुरूप है, जो वर्ग (4-अंकीय) स्तर तक है। राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतिम स्तर (उप-वर्ग) का उपयोग किया गया है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, वित्तीय प्रौद्योगिकी सेवाओं, मध्यस्थता गतिविधियों, आयुष स्वास्थ्य प्रणाली, ई-कॉमर्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था आदि पर विशेष जोर दिया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए एनआईसी-2025 के मसौदे में उप-वर्गों की संख्या एनआईसी-2008 के 1304 से बढ़कर लगभग 1900 हो गई है।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

मिजोरम में रेल लाइन केवल यात्रा नहीं, समृद्धि भी

भारत के उत्तर-पूर्व में स्थित मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने का जश्न मना रहा है। बइरबी-सायरंग रेल लाइन बिछा

जया वर्मा सिन्हा
पूर्व अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड

दी गई है, जो इस ऐतिहासिक बदलाव की गवाह बनेगी। यह लाइन असम-मिजोरम सीमा के पास स्थित बइरबी से शुरू होकर, राजधानी आइजोल से मात्र 18 कि.मी.दूर बसे छोटे नगर सायरंग तक पहुँचती है।

51.38 कि.मी.लंबी यह नई रेल लाइन घने बाँस के जंगलों, गहरी घाटियों और खड़ी पहाड़ियों से गुजरते हुए लुशाई (मिजो) पर्वतों से होकर निकलती है। 45 सुरंगों और 55 मुख्य ब्रिजों वाली इस रेल लाइन पर देश का दूसरा सबसे ऊँचा पियर ब्रिज बना है, जिसकी ऊँचाई 114 मीटर है, यानी कुतुब मीनार से भी अधिक ऊँचा। इसके साथ ही, शांत और सौम्य हवाओं वाली भूमि मिजोरम की राजधानी आइजोल अब राष्ट्रीय रेल ग्रिड से जुड़ गई है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करना आसान नहीं था। दुर्गम स्थलाकृति, भूस्खलन और कठिन मॉनसून जैसी परिस्थितियों ने रेलवे की सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग क्षमता की परीक्षा ली।

नई रेल लाइन मिजोरम के लोगों के जीवन को बदलने जा रही है। अब तक पहाड़ी भू-भाग के कारण आवागमन धीमा और कठिन था, जिससे यहाँ वस्तुएँ महँगी मिलती थीं और यात्राएँ लंबा समय लेती थीं। 51.38 कि.मी. लंबी इस लाइन के पूरा होने से कोलासिब जिले से आइजोल जिले तक की यात्रा का समय आधे से भी कम हो जाएगा। इसका अर्थ है कि सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुओं तक पहुँच आसान होगी, रोजगार और व्यापार के नए अवसर खुलेंगे। यह रेल लाइन उद्यमियों के लिए बड़े बाजारों तक पहुँच के नए रास्ते खोलेगी। आइजोल के लोग अब देश के प्रमुख शहरों तक सुगमता पूर्वक पहुंच सकेंगे। एवं त्योहारों पर उन्हें अपने घर आने-जाने में सुगमता होगी।

प्रकृति और संस्कृति का कॉरिडोर

यह रेल लाइन केवल परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि मिजोरम में विकास और संपर्क के नए दौर का नया अध्याय है। व्यापार और उद्योग के लिए भी यह रेल लाइन मददगार साबित होगी। यहाँ की हरियाली, घाटियाँ और पहाड़ियां दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करेंगी। यहाँ की प्राकृतिक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, आत्मीय आतिथ्य और जीवंत परंपराओं से जुड़ने का अवसर सैलानियों को मिलेगा। मिजोरम की खूबसूरती इसके प्राकृतिक दृश्यों में निहित है- घने जंगल, लहरदार पहाड़, मनमोहक घाटियाँ और स्वच्छ जलधाराएँ व झरने। यही कारण है कि इसे लैंड ऑफ द हाईलैंडर्स और लैंड ऑफ द ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। यह राज्य एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, जहाँ अनोखी वनस्पतियाँ और जीव पाए जाते हैं। यहाँ की आदिवासी संस्कृति अपने संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही, मिजोरम अब एडवेंचर पर्यटन का उभरता हुआ गंतव्य भी बन रहा है। अगस्त 2025 में मिजोरम सरकार और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के बीच इस रेल संपर्क के पर्यटन-संभावनाओं को साकार करने के लिए दो वर्ष का समझौता हुआ। इसमें पर्यटन पैकेजों को राज्य की पर्यटन अवसंरचना से जोड़ने पर बल दिया गया है। आईआरसीटीसी ने 'डिस्कवर नॉर्थ ईस्ट बियोंड गुवाहाटी' पहल के तहत विशेष पर्यटक ट्रेनों का संचालन करने की योजना बनाई है, ताकि किफायती, सतत और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन मॉडल विकसित किया जा सके।

जियो स्ट्रेटजिक ब्रिज

मिजोरम राज्य बांग्लादेश और म्यांमार, दोनों की सीमाओं को साझा करता है। यही कारण है कि यह भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का केंद्र बिंदु है। रेल संपर्क का अर्थ है कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों तरह का व्यापार तेजी से बढ़ेगा। नियोजित रेल और सड़क नेटवर्क का विस्तार मिजोरम को भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच एक प्रमुख परिवहन केंद्र बना सकता है। यह विशेष रूप से वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण है।

परिवर्तन की लहर

आर्थिक और लॉजिस्टिक दृष्टि से हटकर देखें, तो आइजोल में रेल लाइन एक भावनात्मक जुड़ाव की उपलब्धि भी है। मिजोरम के लोगों के लिए यह इस बात की पुष्टि है कि वे देश का अहम हिस्सा हैं और भारत की आकांक्षाओं के केंद्र में हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उद्घाटन की जाने वाली इस नई रेल कनेक्टिविटी के साथ, मिजोरम केवल एक रेलवे परियोजना के पूर्ण होने का अवसर ही नहीं, बल्कि एक लंबे समय से संजोए गए सपने के साकार होने का उत्सव मना रहा है। यह इस सच्चाई का प्रमाण है कि कोई भी भू-भाग इतना कठिन नहीं है और कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है कि समर्पण और दृढ़संकल्प के साथ हासिल न किया जा सके।

पश्चिम रेलवे चलाएगी वडोदरा - गोरखपुर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वडोदरा - गोरखपुर के बीच विशेष किराए पर त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी।विवरण इस प्रकार है:

1. ट्रेन संख्या 09111/09112 वडोदरा - गोरखपुर स्पेशल (साप्ताहिक) [20 फेरे]

ट्रेन संख्या 09111 वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल प्रत्येक शनिवार वडोदरा से 19:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23:30 बजे गोरखपुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 27 सितंबर से 29 नवंबर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09112 गोरखपुर-वडोदरा स्पेशल प्रत्येक सोमवार को गोरखपुर से 05:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:00 बजे वडोदरा पहुँचेगी। यह ट्रेन 29 सितंबर से 01 दिसंबर, 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में गोधरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, शिकोहाबाद, मैनपुरी, फरुर्खाबाद, कानपुर, मानक नगर, बादशाह नगर, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास, द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09111 की बुकिंग 11 सितंबर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे चलाएगी ओखा और शकूर बस्ती (दिल्ली) के बीच स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के त्‍योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से ओखा-शकूर बस्ती (दिल्ली कैंट के पास स्थित) के बीच विशेष किराये पर स्‍पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन संख्या 09523/09524 ओखा-शकूर बस्ती स्पेशल (साप्ताहिक) [20 फेरे]

ट्रेन संख्या 09523 ओखा-शकूर बस्ती स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को ओखा से 10:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10:35 बजे शकूर बस्ती पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 सितंबर से 25 नवंबर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09524 शकूर बस्ती-ओखा स्पेशल प्रत्येक बुधवार को शकूर बस्ती से 13:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13:50 बजे ओखा पहुँचेगी। यह ट्रेन 24 सितंबर से 26 नवंबर, 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में द्वारका, खंभालिया, जामनगर, हापा, राजकोट, सुरेंद्रनगर, विरमगाम, महेसाणा, उंझा, सिद्धपुर, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, गुड़गांव और दिल्ली कैंट स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

ट्रेन संख्‍या 09523 की बुकिंग 11 सितंबर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर मंडल पर मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (DRUCC) की बैठक संपन्न

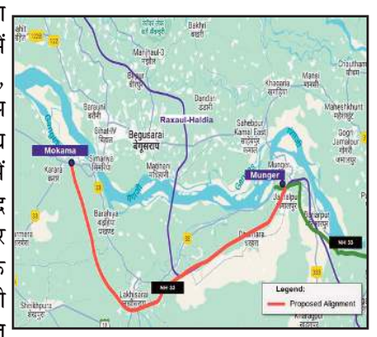

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल पर 10 सितम्बर, 2025 (बुधवार) को मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति (उम्रवउउ) की बैठक का आयोजन मंडल कार्यालय में किया गया। बैठक का शुभारम्भ समिति के सचिव एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया, जिन्होंने उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा मंडल पर अमृत स्टेशन स्कीम के तहत विकसित किये जा रहे स्टेशनों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। बैठक में समिति के अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने भावनगर मंडल पर चल रही प्रमुख गतिविधियों और उपलब्धियों से सदस्यों को अवगत कराया। उन्होंने आश्वस्त किया कि यात्री सुविधाओं का विकास मंडल की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मंडल द्वारा सभी उचित माँगों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा।

बैठक के दौरान पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से भावनगर मंडल की उपलब्धियों एवं यात्री सुविधाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित रेल समस्याओं, नई ट्रेनों के संचालन, परियोजनाओं की शीघ्र पूर्ति तथा स्टेशनों पर बेहतर यात्री सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु बहुमूल्य सुझाव दिए। इस बैठक में समिति के सदस्य श्री बैजु एस. मेहता (भावनगर), श्री महेन्द्र शाह (भावनगर), श्री उपेन्द्रभाई जानी (भावनगर), श्री प्रदीपभाई एच. देसाई (भावनगर), श्री पारसभाई सी. शाह (भावनगर), डॉ. आर. सी. गुप्ता (भावनगर) एवं श्री विजयभाई थानकी (पोरबंदर) उपस्थित रहे। बैठक के समापन पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने सभी सदस्यों का अमूल्य सुझाव देने एवं सक्रिय भागीदारी हेतु आभार व्यक्त किया।

कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन पर भारत-सिंगापुर संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और सिंगापुर पीएसडी ने अपनी प्रस्तुतियाँ साझा कीं। भारतीय पक्ष ने नेक्स्ट जेन सीपीजीआरएएमएस और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए) और सिंगापुर पक्ष ने लाइफ एसजी साझा किया। लाइफ एसजी जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में नागरिकों को सरकारी सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है

(जीएनएस)।

कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन पर भारत-सिंगापुर संयुक्त कार्य समूह की बैठक 10.09.2025 को आयोजित हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से प्रशासनिक सुधार और लोक प्रशासन विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव श्री वी. श्रीनिवास और सिंगापुर की ओर से लोक सेवा प्रभाग की सीईओ सर्विस एसजी सुश्री सेज लिंग लिम ने की। डीएआरपीजी, विदेश मंत्रालय और भारतीय उच्चायोग, सिंगापुर के अतिरिक्त सचिव श्री पुनीत यादव और अन्य अधिकारी तथा लोक सेवा प्रभाग, सिंगापुर का एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल भी संयुक्त कार्य समूह की बैठक में शामिल हुआ। दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रस्तुतियाँ साझा की । भारतीय पक्ष ने नेक्स्ट जेन सीपीजीआरएएमएस और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन (एनईएसडीए) पर प्रस्तुति दी। सिंगापुर पक्ष ने लाइफ एसजी पर प्रस्तुति दी। लाइफ एसजी जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में नागरिकों को सरकारी सेवाओं के एकीकरण हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों के नागरिकों के लाभ के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालियों की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, संस्थागत सहयोग और संयुक्त नवाचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।

भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन खंड (177 किलोमीटर) के दोहरीकरण को कैबिनेट ने मंजूरी दी

कैबिनेट ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 3,169 करोड़ रुपए की लागत से भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट सिंगल रेलवे लाइन खंड (177 किलोमीटर) के दोहरीकरण को मंजूरी दी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भागलपुर-दुमका-रामपुरहाट एकल रेलवे लाइन खंड (177 किमी) के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत लगभग 3,169 करोड़ रुपए है।

इस बढ़ी हुई लाइन क्षमता से परिवहन में सुधार होगा जिससे भारतीय रेलवे की दक्षता और सेवा विश्वसनीयता बढ़ेगी। इस मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्ताव से परिचालन आसान होगा और भीड़भाड़ कम होगी जिससे भारतीय रेलवे के इन सबसे व्यस्ततम खंडों पर आवश्यक बुनियादी ढांचागत विकास संभव होगा। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, जो क्षेत्र के लोगों को व्यापक विकास के माध्यम से "आत्मनिर्भर" बनाएगा और उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा।

ये परियोजनाएं पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई हैं जिनका उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। ये परियोजनाएं रेल यातायात के साथ-साथ सामानों की ढुलाई के लिए भी निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के पांच जिलों को कवर करने वाली इस परियोजना से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 177 किलोमीटर की वृद्धि होगी।

यह परियोजना खंड, देवघर (बाबा बैद्यनाथ धाम), तारापीठ (शक्ति पीठ) आदि जैसे प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करता है।

मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 441 गांवों और 28.72 लाख आबादी तथा तीन आकांक्षी जिलों (बांका, गोड्डा और दुमका) तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

कोयला, सीमेंट, उर्वरक, ईंट और पत्थर आदि जैसी वस्तुओं की ढुलाई के लिए यह एक आवश्यक मार्ग है। इन क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 15 मिलियन टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त माल ढुलाई होगी। रेलवे, पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की लॉजिस्टिक लागत, तेल आयात (5 करोड़ लीटर) और सीओ2 उत्सर्जन (24 करोड़ किलोग्राम) कम करने में मदद करेगा, जो एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

लंबाई 82.4 किलोमीटर और कुल लागत 4447.38 करोड़ रुपये से हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर निर्माण

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज बिहार के बक्सर-भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड मोकामा-मुंगेर खंड के हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) पर निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लंबाई 82.400 किलोमीटर होगी और इसकी कुल पूंजीगत लागत 4447.38 करोड़ रुपये होगी।

यह खंड मोकामा, बड़हिया, लखीसराय, जमालपुर, मुंगेर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शहरों से होकर गुजरता है या उन्हें कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जैसा कि अनुलग्नक-क में दिए गए मानचित्र में दशार्या गया है।

पूर्वी बिहार में मुंगेर-जमालपुर-भागलपुर क्षेत्र आयुध कारखाने (मौजूदा बंदूक कारखाना और रक्षा मंत्रालय द्वारा आयुध कारखाना गलियारे के हिस्से के रूप में प्रस्तावित एक और कारखाना), लोकोमोटिव वर्कशॉप (जमालपुर में), खाद्य प्रसंस्करण (जैसे, मुंगेर में आईटीसी) और संबंधित रसद एवं भंडारण केंद्रों के बल पर एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। भागलपुरी सिल्क (भागलपुर में प्रस्तावित वस्त्र इको-सिस्टम) की प्रमुखता के बीच भागलपुर वस्त्र और रसद केंद्र के रूप में उभर रहा है। वहीं बड़हिया खाद्य पैकेजिंग, प्रसंस्करण और कृषि-गोदाम के लिए एक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इस क्षेत्र में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों से भविष्य में

मोकामा-मुंगेर खंड पर माल ढुलाई और यातायात का विस्तार होने की उम्मीद है।

टोल टैक्स की प्रणाली से युक्त 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर पर 100 किमी/घंटा की डिजाइन स्पीड के साथ वाहन की 80 किमी/घंटा की औसत गति को सपोर्ट करता है। इससे यात्रा में लगने वाला समय लगभग 1.5 घंटे तक कम हो जाएगा। साथ ही, यह यात्री और मालवाहक वाहनों, दोनों के लिए सुरक्षित, तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

82.40 किलोमीटर की प्रस्तावित परियोजना से लगभग 14.83 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 18.46 लाख मानव-दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रस्तावित गलियारे के आसपास के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यह परियोजना अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।

ट्राई ने रेवाड़ी में मोबाइल नेटवर्क की गुणवत्ता का परीक्षण किया

(जीएनएस)।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सामान्य दूरसंचार उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए जुलाई-अगस्त 2025 के दौरान रेवाड़ी शहर (हरियाणा एलएसए में) में आयोजित इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के परिणाम जारी किए हैं। इस ड्राइव टेस्ट का उद्देश्य, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) की मोबाइल नेटवर्क सेवाओं (वॉयस और डेटा दोनों) की वास्तविक गुणवत्ता का आकलन और सत्यापन करना है। आईडीटी के दौरान, ट्राई प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) जैसे कॉल सेटअप सफलता दर, डेटा डाउनलोड और अपलोड गति, आवाज की गुणवत्ता से जुड़े डेटा एकत्र करता है। इन्हें बाद में उपभोक्ताओं को सूचित करने और टीएसपी को अपनी सेवाओं में सुधार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है।

ट्राई ने अपनी नियुक्त एजेंसी के माध्यम से, हरियाणा में 31-07-2025 से 02-08-2025 तक रेवाड़ी में 250.7 किलोमीटर की शहरी ड्राईव परीक्षण, 8 हॉटस्पॉट स्थानों और 1.1 किलोमीटर पैदल परीक्षण किए। ये परीक्षण जयपुर स्थित ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय की देखरेख में किए गए।

रेवाडी शहर में आयोजित ड्राइव टेस्ट में रेवाडी शहर के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर किया गया जिसमें आसपास के क्षेत्र लाखनौर, गोकलघर, सहारनवास, कनमाजारा, बावल, उत्तम नगर, भारावास, शाबाजपुर, जलालपुर, जलियावास, बनीपुर और हरचंदपुर आदि शामिल हैं।

इस प्रकार के ड्राइव परीक्षण में, सभी टीएसपी से 2जी, 3जी, 4जी और 5जी नेटवर्क पर सिम कार्ड का उपयोग करके विभिन्न उपयोग वातावरणों में लाइव डेटा और वॉयस सत्र स्थापित किए जाते हैं, जैसे वाणिज्यिक क्षेत्र, हॉटस्पॉट, सार्वजनिक परिवहन केंद्र आदि। कई उन्नत परीक्षण हैंडसेट का उपयोग किया जाता है और उन्नत सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग करके वास्तविक समय में सत्रों की निगरानी और विश्लेषण किया जाता है।

इस आईडीटी रिपोर्ट के परिणामों को संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ साझा किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे अपने नेटवर्क में सुधार हेतु आगे की कार्रवाई कर सकें। आईडीटी की विस्तृत रिपोर्ट ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी के लिए dv.jaipur@trai.gov.in पर ईमेल भेजा जा सकता है या जयपुर स्थित ट्राई क्षेत्रीय कार्यालय से टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

मुंबई सेंट्रल - बनारस, वडोदरा - गोरखपुर और ओखा - शकूर बस्ती के बीच चलेंगी विशेष किराए पर त्योहार स्पेशल ट्रेनें

मुंबई,

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारी सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मुंबई सेंट्रल - बनारस, वडोदरा - गोरखपुर और ओखा - शकूर बस्ती के बीच विशेष किराए पर त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09083/09084 मुंबई सेंट्रल - बनारस एसी स्पेशल (साप्ताहिक) [16 फेरे]

ट्रेन संख्या 09083 मुंबई सेंट्रल-बनारस स्पेशल प्रत्येक बुधवार को मुंबई सेंट्रल से 23:10 बजे प्रस्थान करेगी और शुक्रवार को 10:30 बजे बनारस पहुँचेगी। यह ट्रेन 17 सितंबर से 5 नवंबर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09084 बनारस-मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को बनारस से 14:30 बजे प्रस्थान करेगी और रविवार को 04:20 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। यह ट्रेन 19 सितंबर से 07 नवंबर 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, शिकोहाबाद, मैनपुरी, भोगाँव, फरुर्खाबाद, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, जंघई और भदोही स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर और एसी-3 टियर (इकोनॉमी) कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09111/09112 वडोदरा - गोरखपुर स्पेशल (साप्ताहिक) [20 फेरे]

ट्रेन संख्या 09111 वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल प्रत्येक शनिवार वडोदरा से 19:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23:30 बजे गोरखपुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 27 सितंबर से 29 नवंबर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09112 गोरखपुर-वडोदरा स्पेशल प्रत्येक सोमवार को गोरखपुर से 05:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:00 बजे वडोदरा पहुँचेगी। यह ट्रेन 29 सितंबर से 01 दिसंबर, 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में गोधरा, रतलाम, कोटा, गंगापुर सिटी, भरतपुर, ईदगाह आगरा, टूंडला, शिकोहाबाद, मैनपुरी, फरुर्खाबाद, कानपुर, मानक नगर, बादशाह नगर, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास, द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 09523/09524 ओखा - शकूर बस्ती स्पेशल (साप्ताहिक) [20 फेरे]

ट्रेन संख्या 09523 ओखा - शकूर बस्ती स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को ओखा से 10:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10:35 बजे शकूर बस्ती पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 सितंबर से 25 नवंबर, 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09524 शकूर बस्ती - ओखा स्पेशल प्रत्येक बुधवार को शकूर बस्ती से 13:15 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13:50 बजे ओखा पहुँचेगी। यह ट्रेन 24 सितंबर से 26 नवंबर 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में द्वारका, खंभालिया, जामनगर, हापा, राजकोट, सुरेंद्रनगर, विरमगाम, महेसाणा, उंझा, सिद्धपुर, पालनपुर, आबूरोड, फालना, मारवाड़, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधी नगर जयपुर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, गुड़गांव और दिल्ली कैंट स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास और द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09083, 09111 एवं 09523 की बुकिंग 11 सितंबर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

नेपाल के बाद फ्रांस की सड़कों पर प्रदर्शन, सैंकड़ों अरेस्ट, खतरे में मैक्रों सरकार?

(जीएनएस) ।पेरिस की सड़कों पर बुधवार को भारी विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध किया, आगजनी की और पुलिस की आंसू गैस का सामना किया। यह आंदोलन राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों पर दबाव बढ़ाने और उनके नए प्रधानमंत्री को चुनौती देने की कोशिश के रूप में सामने आया है। गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलियाओ ने बताया कि राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों के पहले ही कुछ घंटों में लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि, "ब्लॉक एवरीथिंग" (सब कुछ ब्लॉक करो) नामक इस आंदोलन का मकसद पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, फिर भी इसने फ्रांस के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर अड़चने पैदा कर दीं। 80,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह सड़कों को ब्लॉक किया गया और पुलिस को चुनौती दी। पश्चिमी शहर रेन्नेस में एक बस में आग लगा दी गई और दक्षिण-पश्चिम में बिजली की लाइन को नुकसान पहुंचाने के कारण रेल लाइन पर ट्रेनें रुक गईं। गृहमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी "विद्रोह का माहौल" बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, शुरूआती प्रदर्शन पिछले उपद्रवों की तुलना में कम तीव्र नजर आए। पहले मैक्रों को "येलो वेस्ट" आंदोलन, पेंशन सुधारों और पुलिस गोलीकांड के बाद हुए दंगों जैसी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। यह विरोध उस समय हो रहा है जब सोमवार को प्रधानमंत्री फ्रांकोइस बैरो ने संसदीय विश्वास मत खो दिया, जिसके चलते सरकार गिर गई। राष्ट्रपति मैक्रों ने मंगलवार को सेबेस्टियन लेकोर्नू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया, लेकिन विरोध प्रदर्शनों ने तुरंत उन्हें एक चुनौती दे दी।

पृथ्वी विज्ञान सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने महासागर कानून एवं नीति पर 48वें वार्षिक सम्मेलन में हिंद महासागर के सामरिक महत्व, अवसरों और चुनौतियों का उल्लेख किया

नई दिल्ली में आयोजित सीओएलपी48 में, उन्होंने वैश्विक शासन में हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया

भारत ने लगभग 50 वर्षों में पहली बार सीओएलपी48 की मेजबानी की, महासागर शासन में उसकी भूमिका मजबूत हुई

(जीएनएस)।

महासागर कानून एवं नीति पर 48वें वार्षिक सम्मेलन - सीओएलपी48 को आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने मुख्य रूप से संबोधित किया। "महासागरीय शासन के प्रति विकासशील विश्व के दृष्टिकोणः हिंद महासागर क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य" विषय पर आयोजित सम्मेलन में वैश्विक पक्षधारक सागर सीमावर्ती राष्ट्रों की विकासात्मक प्राथमिकताओं पर आधारित संवहनीय और समावेशी समुद्री शासन के उपाय पर विचार के लिए एकत्रित हुए।

सीओएलपी के करीब पांच दशक के इतिहास में पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उपमहाद्वीप में हो रहा है, जो वैश्विक महासागर शासन को आकार देने में भारत की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण है।

सम्मेलन में शामिल गणमान्य प्रतिनिधियों, विद्वानों, नीति निमार्ताओं और पेशेवरों को संबोधित करते हुए, डॉ. रविचंद्रन ने कहा कि पृथ्वी के लिए हिंद महासागर का अद्वितीय महत्व है। उन्होंने कहा कि महासागर जलवायु को नियंत्रित करता है, जैव विविधता को सहारा देता है, आजीविका के साधन बनाए रखता है

और वैश्विक व्यापार तथा सुरक्षा में केंद्रीय भूमिका निभाता है। हालांकि, उन्होंने यह भी आगाह किया कि इस क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अम्लता, घटती उत्पादकता और चक्रवाती तूफानों के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

डॉ. रविचंद्रन ने विकासशील विश्व के परिप्रेक्ष्य में महासागर प्रशासन के लिए पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को रेखांकित किया, जिनमें:

संवहनीय मत्स्य पालन और समुद्री कृषि द्वारा आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच विकासशील देशों की एकजुटता पर आधारित क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ़ करना।

पारंपरिक ज्ञान तथा सहभागी शासन को आधुनिक विज्ञान के साथ समेकित करना।

जैव विविधता सुरक्षित रखने के लिए जलवायु स्थितिअनुकूलता और पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।

महासागर अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और प्रशासन के लिए अभिनव वित्तीय व्यवस्था करना और क्षमता निर्माण, शामिल हैं।

पृथ्वी विज्ञान सचिव ने जोर देकर कहा कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संधारणीय और समावेशी सामुद्रिक अर्थव्यवस्था को आकार देने और मजबूत अधिनियमों, नीतियों और सामूहिक दायित्व की आवश्यकता है।

डॉ. रविचंद्रन ने समुद्री स्थानिक नियोजन, जोखिम न्यूनीकरण ढांचे और स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो अभिनव वित्तीय व्यवस्था और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों द्वारा समर्थित हो, ताकि नवीकरणीय समुद्री ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों और पारिस्थितिकी-पर्यटन जैसे संसाधनों का समुचित और संवहनीय उपयोग किया जा सके।

पृथ्वी विज्ञान सचिव ने कहा कि पृथ्वी की सतह का 70 प्रतिशत हिस्सा समुद्री होने के बाद भी केवल 5 प्रतिशत महासागरों का ही पूरी तरह अन्वेषण हो सका है। उन्होंने इसके लिए उन्नत अनुसंधान, अवलोकन नेटवर्क प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अविलंब आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. रविचंद्रन ने संयुक्त राष्ट्र के समुद्री विनियामक तंत्र - यूएनसीएलओएस, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण और सागर संधि - बीबीएनजे समझौते के अंतर्गत वैश्विक शासन मंचों में हिंद महासागर के देशों की अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया।

उन्होंने हिंद महासागर की विशिष्टता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दुनिया का इकलौता ऐसा महासागर है जहां धाराएं और हवाएं हर छह महीने में अपनी दिशा बदल लेती हैं और इसका ऊर्ध्वतर निकास नहीं है, जिससे ऊष्मा संचित होता है और तेजी से गर्मी बढ़ती है।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने विशाखापत्तनम में आयोजित तीसरे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर सम्मेलन की अध्यक्षता की

(जीएनएस)।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय कुमार सूद ने 9-10 सितंबर, 2025 को विशाखापत्तनम में विजाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर - एएमटीजेड द्वारा आयोजित तीसरे ऑल क्लस्टर्स मीट की अध्यक्षता की। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय-ओपीएसए के वैज्ञानिक सचिव डॉ. परविंदर मैनी और ओपीएसए की सलाहकार/वैज्ञानिक-जी डॉ. राकेश कौर भी विचार-विमर्श में शामिल हुए। आयोजन के दौरान, ओपीएसए के वैज्ञानिक-एफ डॉ. विशाल चौधरी ने 25-26 नवंबर 2024 को हुई पिछली सभा की कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की।

2020 में परिकल्पित, ओपीएसए की विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर पहल क्षेत्र-आधारित नेटवर्क के रूप में, अनुसंधान अनुवाद और नवाचार-आधारित विकास को आगे बढ़ाने के

लिए शिक्षा, उद्योग, सरकार और स्टार्ट-अप के बीच साझेदारी को उत्प्रेरित करता है। यह विभिन्न क्षेत्रगत सहयोग से प्रमुख कार्यक्रम के रूप में परिपक्व हो गया है।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. सूद ने अपने मुख्य भाषण में स्थानीय चुनौतियों, औद्योगिक प्रगति के समाधान और क्षेत्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समूहों की उल्लेखनीय क्षमता का उल्लेख किया। उन्होंने पूरक विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए सुदृढ़ अंतर-क्लस्टर सहयोग को बढ़ावा देकर क्लस्टर पारिस्थितिकी तंत्र की प्रभावशीलता और वैश्विक स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया।

वैज्ञानिक सचिव ने बताया कि आठ सक्रिय क्लस्टरों में से पांच अपने परिचालन के दूसरे चरण में पहुंच गये हैं, जहां औद्योगिक साझेदारी पर पूर्ण जोर दिया जा रहा है। उन्होंने उद्योग और शिक्षा जगत के बीच गतिशील अंतसंर्बंधों का उल्लेख किया, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है, शोध परिणामों के अनुवाद बेहतर होते हैं और सुनिश्चित होता है कि हमारे वैज्ञानिक प्रयास से व्यावसायीकरण की संभावनाओं को गति मिले।

एस्परगिलस सेक्शन निगरी में छिपी विविधता की पहचान

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एस्परगिलस सेक्शन निगरी में छिपी विविधता की पहचान : भारत के पश्चिमी घाट से दो नई प्रजातियों का परिचय

(जीएनएस)।

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान , पुणे स्थित एमएसीएस-अगरकर अनुसंधान संस्थान के शोधकताओं ने एस्परगिलस सेक्शन निगरी (जिसे आमतौर पर ब्लैक एस्परगिलस के रूप में जाना जाता है) की दो नई प्रजातियों, एस्परगिलस ढाकेफाल्करी और एस्परगिलस पेट्रीसियाविल्टशायरी की पहचान की है और पश्चिमी घाट से एकत्र किए गए मिट्टी के नमूनों से दो ब्लैक एस्परगिलस ए. एक्यूलेटिनस और ए. ब्रुनेओवियोलेसियस का पहला भौगोलिक रिकॉर्ड दर्ज किया है।

ये निष्कर्ष इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हॉटस्पॉट के निरंतर अन्वेषण और संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, जिसका वैज्ञानिक, पारिस्थितिक और जैव-प्रौद्योगिकी दृष्टि से अत्यधिक महत्व है।

एस्परगिलस वंश तंतुमय कवकों के एक विविध समूह से बना है जो विभिन्न पारिस्थितिक क्षेत्रों में सर्वत्र वितरित हैं और जिनका चिकित्सीय, औद्योगिक और पारिस्थितिक महत्व बहुत अधिक है। हालांकि पश्चिमी घाट से कई एस्परगिलस प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है लेकिन एस्परगिलस खंड निगरी के सदस्यों पर विशेष रूप से केंद्रित रिपोर्टें सीमित हैं, जो इस क्षेत्र में इस खंड के भीतर आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके

आगे व्यवस्थित अन्वेषण और वर्गीकरण संबंधी जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

एस्परगिलेसी परिवार के व्यवस्थित विज्ञान के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कड़े स्वर्ण मानक प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं; एस्परगिलस में प्रजातियों के प्रमाणीकरण के लिए एकीकृत या बहु-चरणीय वर्गीकरण दृष्टिकोण । इस बहु-चरणीय वर्गीकरण दृष्टिकोण को अपनाते हुए शोध दल ने आईटीएस और सीएएम (पहचान के लिए जीन), बीईएनए और आरपीबी2 (फाइलोजेनी के लिए जीन) का उपयोग करके विस्तृत रूपात्मक लक्षण वर्णन को आणविक फाइलोजेनेटिक विश्लेषणों के साथ जोड़ा। बहु-जीन फाइलोजेनेटिक विश्लेषण का अनुमान अधिकतम संभाव्यता विश्लेषणों (उच्च सांख्यिकीय समर्थन के साथ) के माध्यम से लगाया गया और दो नई प्रजातियों की विशिष्ट वंशावली की पहचान की गई।

ब्लैक एस्परगिलस को औद्योगिक अनुप्रयोगों में विशेष रूप से साइट्रिक अम्ल उत्पादन, खाद्य कवक विज्ञान, किण्वन प्रौद्योगिकी और कृषि में सर्वाधिक उपयोगी माना जाता है। यह सूची भारत से एस्परगिलस सेक्शन निग्री की फॉस्फेट घुलनशील क्षमता पर आधारित एक शोध थीसिस का भी हिस्सा है। ए. ढाकेफाल्करी की विशेषता तीव्र कॉलोनी वृद्धि है, जो हल्के से गहरे भूरे रंग के कोनिडिया और पीले-सफेद से पीले-नारंगी रंग के स्क्लेरोटिया का निर्माण करती है। इसके एक-श्रेणीबद्ध कोनिडियोफोर दो से तीन स्तंभों में विभाजित होते हैं और इसमें चिकनी दीवारों वाले, दीर्घवृत्ताकार कोनिडिया होते हैं, जो इसे संबंधित प्रजातियों से अलग करते हैं जिनमें आमतौर पर गोलाकार, एकिनुलेट कोनिडिया होते हैं।

चित्र 1: एस्परगिलस ढाकेफाल्करी

ए. पेट्रीसियाविल्टशायरी भी जापेक यीस्ट ऑटोलाइसेट अगर (सीवाईए) और माल्ट एक्सट्रेक्ट अगर (एमईए) पर प्रचुर मात्रा में स्क्लेरोटिया वाली तेजी से बढ़ने वाली कॉलोनियां प्रदर्शित करता है, हालांकि इसमें बीजाणु निर्माण कम होता है। सीआरईए में अम्ल उत्पादन मौजूद होता है और यह सीवाईए, एमईए और ओए पर पीले-नारंगी स्क्लेरोटिया उत्पन्न करता है। इसमें इचिनुलेट कोनिडिया और यूनिसेरिएट कोनिडियोफोर होते हैं जो पांच से अधिक स्तंभों में शाखाबद्ध होते हैं।

चित्र 2: एस्परगिलस पेट्रीसियाविल्टशायरी

फाइलोजेनेटिक विश्लेषण ए. ढाकेफाल्करी को ए. सैक्रोलिटिकस की एक बहन प्रजाति के रूप में रखता है, जबकि ए. पेट्रीसियाविल्टशायरी ए. इंडोलोजेनस , ए. जैपोनिकस और जैपोनिकस श्रृंखला के ए. यूवारम से निकट संबंधी है। इसके अतिरिक्त अध्ययन में भारत में ए. एक्यूलेटिनस और ए. ब्रुनेओवियोलेसियस के पहले रिकॉर्ड की रिपोर्ट दी गई है।

पश्चिमी घाटों से एस्परगिलस सेक्शन निगरी के भीतर नवीन प्रजातियों की पिछली खोज विदेशी शोधकताओं द्वारा की गई थी।

'जिलों के समग्र विकास' पर राष्ट्रीय सम्मेलन 11-12 सितंबर 2025 को पटना में आयोजित किया जाएगा

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री उद्घाटन सत्र में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे

जिला कलेक्टरों और राज्य/केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 20 से अधिक वक्ता पुरस्कृत सर्वोत्तम परिपाटियां प्रस्तुत करेंगे

राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य देश भर के जिलों में अपनाई गई नवीन शासन परिपाटियों का प्रसार करना है

(जीएनएस)।

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), बिहार सरकार के सहयोग से, 11-12 सितंबर, 2025 को पटना में ह्लजिलों के समग्र विकासह्व विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

माननीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे उद्घाटन भाषण भी देंगे। सम्मेलन में उन शासन मॉडलों को प्रदर्शित किया जाएगा जिन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हुई है।

प्रशासनिक सुधार और लोक

शिकायत विभाग में सचिव श्री वी. श्रीनिवास और बिहार सरकार में मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इससे विचारों और परिपाटियों के आकर्षक आदान-प्रदान का वातावरण बनेगा।

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत और चयनित पहल 2023 और 2024 (जिलों का समग्र विकास), प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत पहल 2023 और 2024 (शासन में नवाचार) और बिहार सरकार में नवाचारों पर प्रस्तुतियाँ दी जाएँगी। इनमें समग्र विकास, डिजिटल शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण परिवर्तन और लोक सेवा वितरण जैसी कई श्रेणियाँ शामिल होंगी। प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत पहल 2024 पर फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी।

राष्ट्रीय सम्मेलन का पहला सत्र प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत/चयनित पहल 2023 और 2024 (शासन में नवाचार) पर आधारित होगा। इस सत्र की अध्यक्षता प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अपर सचिव श्री पुनीत यादव करेंगे। इसमें जिला-स्तरीय नवाचारों पर चर्चा की जाएगी।

राष्ट्रीय सम्मेलन में ऐसे चार सत्र और होंगे। इनकी अध्यक्षता वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, जिनमें बिहार के लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री नर्मदेश्वर लाल; आईआईपीए, नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ. एस. एन. त्रिपाठी; और प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती सरिता चौहान शामिल हैं। इस दौरान विभिन्न राज्यों के जिला-स्तरीय नवाचारों पर प्रस्तुतियाँ दी जाएँगी। इसके अलावा बिहार सरकार में नवाचारों पर समर्पित सत्र भी होगा।

इस सम्मेलन में भारत भर से 300 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इनमें वरिष्ठ प्रशासक, क्षेत्र विशेषज्ञ और लोक प्रशासन के क्षेत्र के पेशेवर शामिल होंगे।

राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य देश भर के जिलों द्वारा अपनाई गई ऐसी नवीन शासन पद्धतियों को प्रदर्शित और प्रसारित करना है, जिनसे सेवा वितरण, नागरिक कल्याण और स्थानीय विकास के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य जिला कलेक्टरों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निमार्ताओं और विशेषज्ञों को अनुभव साझा करने, विचार-विमर्श करने एवं प्रमुख योजनाओं की पूर्णता, विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत विकास और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करना है। सहयोग और पारस्परिक ज्ञान को बढ़ावा देकर, यह सम्मेलन सफल मॉडलों को संस्थागत रूप देने, प्रभावशाली पहलों को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर समावेशी और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में भारत की यात्रा को गति देने का प्रयास है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने चौथे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की तैयारी आरंभ की

(जीएनएस)।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) देश के सभी 1600 जिलों और प्रमंडल मुख्यालयों में 1 से 30 नवंबर 2025 तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अभियान चलाएगा।

इस सिलसिले में पेंशन सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2025 को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें 19 पेंशन वितरण बैंकों और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में तीसरे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान की प्रदर्शन समीक्षा की गई। पिछले अभियान के

दौरान एक करोड़ 62 लाख डीएलसी प्राप्त किए गये, जिनमें 50 लाख से अधिक डीएलसी फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक (बायोमेट्रिक तरीके से चेहरे की पहचान) के माध्यम से बनाए गए। इसके अलावा, बैंकों, आईपीपीबी, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और पेंशनभोगी कल्याण संघों (पीडब्ल्यूए) की सक्रिय भागीदारी से 800 से अधिक जिलों और शहरों में 1,900 शिविर आयोजित किए गए।

बैठक में भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री अमृतेश मोहन, पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री राजेश प्रसाद और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री गुरुशरण राय बंसल तथा पेंशन वितरण करने वाले अन्य बैंकों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने अपने नेटवर्क और डोरस्टेप सेवा चैनलों (ग्राहकों को घर पर ही आवश्यक सेवाओं का लाभ देने) की पूरी तैयारी का आश्वासन दिया।

बैठक में नवंबर 2025 के लिए दैनिक स्तर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार किये जाने के लक्ष्य, 1600 जिलों और प्रमंडल मुख्यालयों पर शिविरों का समय निर्धारण और अत्यंत वरिष्ठ और अलग-अलग श्रेणी के दिव्यांग पेंशनरों के लिए डोरस्टेप सेवाओं के प्रावधान को अंतिम रूप दिया गया। हितपक्षधारकों ने कार्य की वास्तविक समय में निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए डीएलसी एनआईसी पोर्टल के इस्तेमाल पर सहमति व्यक्त की। बैंक और आईपीपीबी अक्टूबर 2025 में एसएमएस, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, बैनर और स्थानीय मीडिया प्रचार द्वारा पेंशनरों को निवेदन विकल्पों के बारे में सूचित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान आरंभ करेंगे।

चौथा डीएलसी अभियान पेंशनभोगियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी आउटरीच पहल होगी। इसका लक्ष्य 2 करोड़ डीएलसी तैयार करना है। इसमें चेहरे से प्रमाणीकरण तकनीक पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे पेंशनभोगियों को सार्वभौमिक कवरेज और जीवन सुगमता सुनिश्चित होगी।

भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की लंबी दूरी हेतु प्रशिक्षण के लिए तैनाती

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन (1टीएस) के जहाज आईएनएस तीर और आईसीजीएस सारथी व आईएनएस शार्दुल दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में 08 सितंबर, 2025 को क्रमशः ला रियूनियन तथा पोर्ट लुईस पहुंचे।

ला रियूनियन में तिर व सारथी का स्वागत फ्रांसीसी नौसेना के जहाज एफएस निवोस द्वारा किया गया और स्वागत के दौरान एक सयुंक्त नौसैन्य अभ्यास (पैसेक्स) भी आयोजित किया गया। इस यात्रा में क्रॉस-ट्रेनिंग दौरे, संयुक्त डाइविंग अभ्यास, योग सत्र और खेलकूद जैसी प्रमुख गतिविधियां शामिल हैं, जिससे भारत-फ्रांस नौसैनिक साझेदारी सशक्त होगी। 1टीएस के वरिष्ठ अधिकारी ने फ्रांसीसी नौसेना बेस कमांडर और कमांडेंट सुपीरियर डेस एफएजेडएसओआई से भी मुलाकात की, जहां चर्चा क्षेत्रीय सुरक्षा, संयुक्त अभ्यासों की भविष्य की संभावनाओं तथा मित्रवत संबंधों को विस्तार देने के साझा दृष्टिकोण के तहत समुद्री सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर केंद्रित रही।

इसके साथ ही आईएनएस शार्दुल ने मॉरीशस के पोर्ट लुईस में प्रवेश किया, जहां उसने आगमन से पहले एमसीजीएस विक्ट्री और मॉरीशस तटरक्षक डोर्निंयर के साथ संयुक्त गश्त एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) निगरानी की। बंदरगाह पर प्रवास के दौरान, आईएनएस शार्दुल के कमांडिंग ऑफिसर ने पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय तटरक्षक बल के कमांडेंट और गृह मामलों के सचिव सहित मॉरीशस के वरिष्ठ नेतृत्व से भेंट की। इस बातचीत से भारत और मॉरीशस के बीच विश्वास, व्यावसायिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संबंधों के मूल्यांवान बंधन की पुष्टि हुई।

मॉरीशस के राष्ट्रीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है, जिसमें गोताखोरी संचालन, अग्निशमन, क्षति नियंत्रण और जहाज पर परिचयात्मक अभ्यास शामिल हैं। सौहार्द और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक आउटरीच, योग सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा मैत्रीपूर्ण खेल आयोजनों का आयोजन किया जा रहा है। क्रॉस-डेक दौरे, स्कूल भ्रमण और खुले जहाज के कार्यक्रम, आम जनता व प्रवासी भारतीयों को समुद्री जीवन एवं भारतीय नौसेना की भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेंगे।

ला रियूनियन और मॉरीशस में पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के समवर्ती बंदरगाह आगमन से साझेदार देशों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता उजागर होती है। यह तैनाती क्षेत्रीय स्थिरता, संवर्धित आपसी सहभागिता और महासागर के दृष्टिकोण के अनुरूप घनिष्ठ सहयोग की साझा आकांक्षाओं को भी दशार्ती है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में मैत्री सेतु को सशक्त करने में भारतीय नौसेना की भूमिका की पुष्टि करती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सामाजिक, कल्याण और सुरक्षा क्षेत्रों में सुधार उपायों की पहचान के लिए परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया

(जीएनएस)।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 9 सितंबर को सामाजिक, कल्याण और सुरक्षा क्षेत्रों में सुधार उपायों की पहचान पर एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया।

कार्यशाला की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मलिक ने की। इस सत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधिमंडलों ने सक्रिय भागीदारी की।

यह विचार-विमर्श, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत सुधारों पर केंद्रित था जिनमें पोषण और ईसीसीई वितरण में सुधार, मिशन शक्ति - महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करना और मिशन वात्सल्य - बच्चों के समग्र विकास और संरक्षण को सुनिश्चित किए जाने के लक्ष्य रखे गए हैं।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों ने अंतिम छोर तक

सेवा पहुंचाने तथा महिला एवं बाल-केंद्रित विकास सुनिश्चित करने के लिए विधायी, नीति, प्रक्रियागत और संस्थागत सुधारों पर बहुमूल्य जानकारी साझा की।

इस कार्यशाला के माध्यम से सहयोगात्मक सुधार उपायों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 'सबसे पहले महिला एवं बाल-बालिका' दृष्टिकोण की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।